RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 31 MARCH TO 06 APRIL 2021 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 06 ■ अंक 32 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

ऑटोमेटिक पेमेंट के नए नियम लागू करने के लिए RBI ने बढ़ाई आखिरी तारीख Page 3

1 अप्रैल से बोतलबंद पानी बेचना नहीं होगा आसान Page 5

देश के कई राज्यों में बीयर की बिक्री में बंपर उछाल, जानिए क्या है असली वजह Page 7

editoria!

बदल रहे हैं समीकरण

चीन और ईरान के बीच बीते शनिवार को हुआ 25 वर्षीय समझौता न केवल इस पूरे इलाके की भू-राजनीति को बल्कि दीर्घकालिक अंतरराष्ट्रीय समीकरणों को भी बहुत गहराई से प्रभावित करने वाला है। समझौते के मुताबिक ईरान में चीन अगले 25 वर्षों में 40,000 करोड़ डॉलर का निवेश करने वाला है। बदले में उसे ईरान से सस्ती कीमत पर भारी मात्रा में तेल की सप्लाई मिलती रहेगी। ध्यान रहे, ईरान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। विश्व के कुल तेल भंडार का 10 फीसदी उसके पास है। ईरान और चीन दोनों अभी अलग-अलग स्तरों पर अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के कार्यकाल में लगाए गए प्रतिबंधों के चलते ईरान अपना तेल नहीं बेच पा रहा है, हालांकि राष्ट्रपति जो बाइडेन के पदभार ग्रहण करने के बाद इन प्रतिबंधों के शिथिल होने की संभावना बढ़ी है। दोनों पक्षों में इस पर बातचीत भी चल रही है, लेकिन अभी तक सहमति नहीं बनी है। अमेरिका प्रतिबंध उठाए जाने से पहले ईरान से अपनी कुछ शर्तें मनवाना चाहता है जबकि ईरान का कहना है कि पहले प्रतिबंध उठाए जाएं तभी बाकी मुद्दों पर विचार किया जा सकता है। इस बीच समझौते पर दस्तखत होने से कुछ ही दिन पहले चीन और रूस, दोनों ने अमेरिका से आग्रह किया कि वह जितनी जल्दी हो सके ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध बिना शर्त वापस ले। जाहिर है, चीन के साथ समझौते के बाद ईरान और अमेरिका में प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया को लेकर सहमति बनना पहले के मुकाबले कठिन हो गया है। बहरहाल, इस समझौते का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू एक रणनीतिक गोलबंदी का है। चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की का आकार लेता हुआ गठबंधन वैसे तो अमेरिका के खिलाफ है, लेकिन मौजूदा समीकरणों को देखते हुए भारत के भी कुछ अहम हित इससे प्रभावित हो सकते हैं। खासकर इसलिए भी कि पिछले कुछ समय से अमेरिका और भारत की बढ़ती नजदीकी ने रूस जैसे मित्र देश को आशंकित कर दिया है। दूसरी बात यह कि चीन अगर अगले 25 वर्षों तक ईरान में टेक्नॉलजी, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस आदि क्षेत्रों में भारी निवेश करने वाला है तो इसका मतलब यह हुआ कि ईरान की उस पर निर्भरता बढ़ेगी और आने वाले दौर में वह चीन के एक विश्वस्त सहयोगी के रूप में उभरेगा। उसके माध्यम से चीन न केवल पश्चिम एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास करेगा बल्कि अफगानिस्तान और मध्य एशिया में भारत के लिए मौजूद अवसरों को कम करके कश्मीर में भारत की मुश्किलें बढ़ाएगा। ईरान के चाबहार पोर्ट और उसे फीड देने वाली परिवहन व्यवस्था को विकसित करने में भारत अपनी काफी पूंजी लगा चुका है। देखना होगा कि चीन-ईरान समझौते का कोई विपरीत प्रभाव इसपर न पड़े। कुल मिलाकर यह समझौता भारतीय राजनय के लिए कई मोर्चों पर कठिन चुनौतियां लेकर आया है।

1 अप्रैल से आयकर रिटर्न भरने का नया नियम

बच नहीं पाएंगे टैक्स चोर

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

कोरोना महामारी के चलते वित्त वर्ष 2019-20 का संशोधित या विलंबित आईटीआर भरने की मियाद बढ़ा दी गई थी। हालांकि, एक बार फिर से केंद्र सरकार ने वित्त विधेयक-2021 के तहत नियम में बदलाव किया है। इसके अनुसार, अगर आप देरी से आयकर रिटर्न भरते हैं तो 1 अप्रैल, 2021 से अधिक विलंब शुल्क देना होगा।

मौजूदा नियम के तहत अगर करदाता आकलन वर्ष का रिटर्न मार्च तक भरने के लिए स्वतंत्र थे। वहीं, इसके बाद दिसंबर तक भरने पर 5000 रुपये का शुल्क और मार्च के अंत तक 10,000 रुपये का शुल्क देना पड़ता था। लेकिन अप्रैल से शुरू होने से यह सुविधा खत्म हो जाएगी। कर दाताओं के पार 10000 रुपये देकर बीते वित्त वर्ष का रिटर्न भरने की सुविधा मार्च तक नहीं रहेगी। यह सुविधा दिसंबर तक ही खत्म हो जाएगी। इस अवधि के लिए शुल्क 5000 रुपये ही होगी। हालांकि, अगर आपकी आय पांच लाख रुपये तक है तो आपको 1,000 रुपये का ही शुल्क देना होगा।

रिफंड की प्रक्रिया जल्द पूरी करने की कवायद

कर विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम रिफंड की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए उठाया गया है। गौरतलब है कि आयकर विभाग रिफंड जल्द से जारी करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इस दिशा में कई बदलाव भी विभाग ने किए है। हाल ही में विभाग ने आयकर रिटर्न के साथ आधार नंबर नहीं देने पर 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

रिटर्न नहीं भरने पर नोटिस भी संभव

विशेषज्ञों के अनुसार, अगर आपने तय समय तक आयकर दाखिल नहीं किया है तो आयकर विभाग आपको नोटिस भी भेज सकता है, अगर उसे मालूम होता है कि आपके पास कर योग्य आय है। ऐसे मामलों में, आपको विलंबित अवधि के लिए ब्याज के साथ देय कर राशि पर जुर्माना का भी भुगतान करना पड़ सकता है। ऐसे में अगर किसी करदाता के पास कर योग्य आय है, लेकिन वह रिटर्न नहीं भरता है तो बाद ने मुश्किल हो सकती है।

कर चोरी करना मुश्किल होगा

अब तक करदाता कर बचाने या अन्य कारणों से शेयर ट्रेडिंग या म्युचुअल फंड निवेश के बारे में खुलासा नहीं करते थे। अब आयकर विभाग के अधिकारी सीधे आपके ब्रोकरेज हाउस, एएमसी या पोस्ट ऑफिस से इन चीजों के बारे में जानकारी लेंगे, इसलिए करदाता के लिए अपनी आय के स्रोत और निवेश के बारे में जानकारी छिपाना मुश्किल होगा।

कौन देगा आपकी जानकारी

आयकर की धारा 114 ई के तहत बचत योजना में जमा रकम विशेष फंड ट्रासफर (एसएफटी) में आते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी निवेशक ने म्युचुअल फंड बेचकर लाभ कमाया है, तो फंड हाउस उसके खाते की जानकारी आयकर विभाग तक पहुंचाएंगे। बैंक या डाकघर की बचत योजनाओं में जमा रकम पर मिले ब्याज की जानकारिया भी आयकर विभाग को देंगे। इसी तरह शेयर बाजार, कंपनिया, म्यूचुअल फंड हाउस, डाकघर आदि भी देंगे।

भारत दिखाएगा सऊदी अरब को आईना, शर्तें पूरी करने वाले देश से ही खरीदेगा कच्चा तेल

नई दिल्ली। एजेंसी

सऊदी अरब ने कच्चे तेल के उत्पादन नियंत्रण को कम करने के भारत के रिक्वेस्ट को नजरअंदाज कर दिया है। ऐसे में भारत ने कहा है कि वह कच्चे तेल की खरीद किसी ऐसे देश से करेगा, जो उसके मुताबिक कारोबारी शर्तों के साथ सस्ती दरों की पेशकश करेगा। न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक देश भारत की रिफाइनरी कंपनियां सप्लाई में विविधीकरण के लिए पश्चिम एशिया के बाहर से अधिक तेल की खरीद कर रही हैं। खबर के मुताबिक, फरवरी में अमेरिका, सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया था। लेकिन यह पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन और उसके दूसरे सहयोगियों (ओपेक प्लस) के उत्पादन में कड़ाई बरतने के 4 मार्च के फैसले से पहले की बात है। एक कार्यक्रम में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इम्पोर्ट पर फैसले से पहले भारत अपने हितों का

ध्यान रखेगा। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री अब्दुलअजीज बिन सलमान ने भारत से कहा था कि वह उत्पादकों से उत्पादन बढ़ाने को कहने के बजाय पिछले साल बेहद निचली कीमत पर खरीदे गए कच्चे तेल के इस्तेमाल करे। प्रधान ने कहा कि सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री का यह बयान एक 'नजदीकी मित्र' का 'अकूटनीतिक' वक्तव्य है। प्रधान ने कहा कि भारत रणनीतिक और आर्थिक फैसले करते समय अपने हितों को ध्यान में रखेगा। उन्होंने कहा कि हम उपभोक्ता देश हैं और हमें लंबी अवधि के लिए ऊर्जा का आयात करना है। ऐसे में जो भी देश हमें सस्ता कच्चा तेल आसान शर्तों के साथ देगा, हम उसे खरीदेंगे। प्रधान ने कहा कि किसी भी देश द्वारा सस्ती दरों पर सप्लाई हमारी प्राथमिकता है। यह कोई भी देश हो सकता है। यह पूछे जाने पर कि क्या फरवरी का आयात का रुख यह दर्शाता है कि भारत, सऊदी अरब के ऊपर अमेरिका को तरजीह दे रहा है, पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि यह मुद्दा नहीं है कि हम किसके नजदीक हैं और किसके नहीं। मुद्दा यह है कि कौन हमारे हितों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकता है।

भारत की मुद्रास्फीति संतोषजनक स्तर से कहीं अधिक ऊंची: मूडीज एनालिटिक्स

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत की मुद्रास्फीति संतोषजनक स्तर से काफी ऊंची है और एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में यह अपवाद है। मूडीज कॉरपोरेशन की अनुषंगी इकाई मूडीज एनालिटिक्स ने मंगलवार को यह कहा। जोखिम, प्रदर्शन आदि से संबंधित आर्थिक शोध उपलब्ध कराने और परामर्श देने वाली मूडीज एनालिटिक्स ने कहा कि ईंधन के ऊंचे दाम खुदरा महंगाई दर पर दबाव बनाये रखेंगे। इससे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के लिये नीतिगत दर में आगे कटौती मुश्किल होगी। खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी में बढ़कर 5 प्रतिशत पहुंच गयी जो जनवरी में 4.1 प्रतिशत थी। रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति पर विचार करते समय मुख्य रूप से खुदरा मुद्रास्फीति पर गौर करता है। मूडीज एनालिटिक्स ने कहा कि मुख्य मुद्रास्फीति (खाद्य, ईंधन और प्रकाश की महंगाई दर को छोड़कर) फरवरी में बढ़कर 5.6 प्रतिशत रही जो जनवरी में 5.3 प्रतिशत थी। उसने कहा कि भारत में मुद्रास्फीति काफी ऊंची है। उसने

अपनी रिपोर्ट में कहा कि एशिया के ज्यादातर देशों में मुद्रास्फीति नरम है और तेल के दाम में वृद्धि तथा अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे खोले जाने से 2021 में इसमें तेजी की आशंका है। इस साल वैश्विक मानिक ब्रेंट कच्चा तेल 26 प्रतिशत उछलकर 64 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। कोविड-19 संकट जब अपने चरम के करीब था, यह मार्च 2020 में 30 डॉलर प्रति बैरल था। मूडीज एनालिटिक्स के अनुसार, ''मुद्रास्फीति के मामले में भारत और फिलीपीन अपवाद हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रस्फीति संतोषजनक स्तर से कहीं ऊपर है। इससे नीतिनिर्माताओं के लिये चुनौतियां बढ़ रही हैं।''

उसने कहा कि भारत की मुद्रास्फीति चिंताजनक है। खाद्य वस्तुओं के दाम में उतार-चढ़ाव और तेल के दाम में तेजी से खुदरा महंगाई दर 2020 में कई बार उच्च सीमा 6 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गयी। इससे रिजर्व बैंक के लिये नीतिगत दर में और कटौती मुश्किल हो रही है। मौद्रिक नीति व्यवस्था के तहत आरबीआई को मुद्रास्फीति 2 प्रतिशत घट-बढ़ के साथ 4 प्रतिशत पर बरकरार रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है। मूडीज एनालिटिक्स ने यह भी कहा, ''आरबीआई मुद्रास्फीति को इस दायरे में रखने के लक्ष्य को 31 मार्च की मौजूदा समयसीमा के बाद भी बनाये रख सकता है।''

कच्चे तेल के औसत दाम औसतन 65 डॉलर होने पर, हो सकता है रिलायंस-अरामको करार: रिपोर्ट

नई दिल्ली। एजेंसी

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट तथा अरामको की वार्षिक 75 अरब डॉलर का लाभांश देने की प्रतिबद्धता के चलते सऊदी अरब की कंपनी के रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. के साथ सौदे में विलंब हुआ है। अरामको द्वारा रिलायंस की तेल-से-रसायन इकाई (ओ2सी) में हिस्सेदारी खरीदी जानी है, लेकिन यह सौदा पूरा नहीं हो पाया है। अनुसंधान कंपनी जेफ्रीज की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी ने अगस्त, 2019 में घोषणा की थी कि ओ2सी कारोबार में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री के लिए बातचीत चल रही है। इसमें गुजरात के जामनगर की दो तेल रिफाइनरियां और पेट्रोरसायन परिसंपत्तियां शामिल हैं। यह सौदा मार्च, 2020 तक पूरा होना था, लेकिन इसमें विलंब हुआ। हालांकि, दोनों ही कंपनियों ने विलंब की कोई वजह नहीं बताई है। जेफ्रीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि कच्चे तेल की दिग्गज सऊदी अरामको ने हाल में भारत और चीन में मूल्यवर्धन की उत्तरवर्ती कड़ियों में निवेश पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। रिलायंस के ओ2सी कारोबार में निवेश के जरिये वह चीन में इस मॉडल को दोहराना चाहती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और अरामको की 75 अरब डॉलर की लाभांश की प्रतिबद्धता की वजह से इस सौदे में विलंब हुआ है। ''हमारा विचार है कि कच्चे तेल के 65 डॉलर प्रति बैरल के दाम यह सौदा होने की दृष्टि से पर्याप्त हैं।''

सरकार ने एक अप्रैल से चुनावी बॉन्ड जारी करने को दी मंजूरी

नई दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने चार राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनावों के बीच मंगलवार को चुनावी बॉन्ड की 16वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी। यह बिक्री के लिये एक अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच खुलेगा। राजनीतक दलों को दिये जाने वाले चंदे में पारदर्शिता लाने के प्रयास के तहत चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था की गयी है। इसके तहत राजनीतिक दलों को नकद चंदे के बजाए चुनावी बॉन्ड का विकल्प रखा गया है। हालांकि विपक्षी दल ऐसे बॉन्ड के जरिये चंदे में कथित पारदर्शिता की कमी को लेकर चिंता जताते रहे हैं।

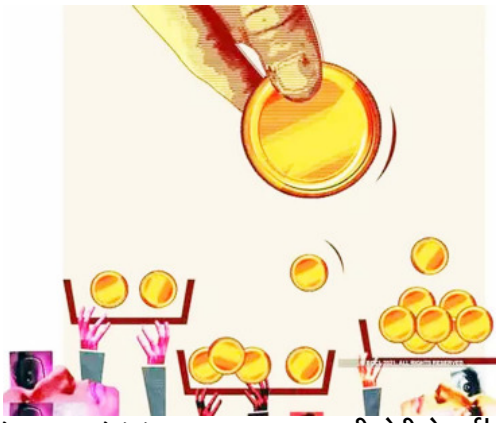

ध्यान रखनी होगी ये शर्त!

वित्त मंत्रालय ने एक बयान मेंकहा कि निर्वाचन आयोग ने 17 मार्च को आचार संहिता के दृष्टकोण से कुछ शर्तों के साथ चुनावी बॉन्ड को मंजूरी दे दी। इसमें यह शर्त शामिल है कि कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता या पदाधिकारी सार्वजनिक भाषण या प्रेस अथवा अपने उन क्षेत्र के लोगों से इस संदर्भ में कुछ नहीं कहेंगे, जहां चुनाव होने जा रहे हैं।

29 शाखाओं से होगी बिक्री

बयान के अनुसार, ''भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को एक अप्रैल 2021 से 10 अप्रैल 2021 के दौरान 29 अधिकृत शाखाओं के जरिये चुनावी बॉन्ड की 16वें चरण की बिक्री और उसे भुनाने के लिये अधिकृत किया गया है।'' एसबीआई की ये 29 शाखाएं कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, तिरूवनंतपुरम, पटना, नयी दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, श्रीनगर, देहरादून, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर, मुंबई और लखनऊ जैसे शहरों में हैं। पहले चरण में चुनावी बॉन्ड की बिक्री एक से 10 मार्च 2018 को हुई थी। चुनाव बॉन्ड की 15वें चरण की बिक्री एक जनवरी से 10 जनवरी 2021 के बीच हुई थी। योजना के प्रावधान के अनुसार चुनावी बॉन्ड कोई व्यक्ति खरीद सकता है जो भारत का नागरिक या यहां गठित इकाई है। वैसे पंजीकृत दल जिन्होंने पिछले लेकसभा या विधानसभा चुनाव में कम-से-कम एक प्रतिशत वोट हासिल किया है, वे चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के हकदार हैं। एसबीआई एक मात्र बैंक है जिसे इस प्रकार के बॉन्ड जारी करने के लिये अधिकृत किया गया। चुनावी बॉन्ड जारी करने के 15 दिनों के भीतर वैध रहता है। वैधता अवधि समाप्त होने के बाद अगर बॉन्ड जमा किया जाता है, तो उसे संबंधित राजनीतिक दल को भुगतान नहीं किया जाएगा। पात्र राजनीतिक दलों द्वारा जमा बॉन्ड की राशि उसी दिन उसके खाते में आ जाएगी।

डीजीसीए ने ग्रीष्मकालीन समयसारिणी के लिए प्रति सप्ताह 18,843 उड़ानों को मंजूरी दी

नई दिल्ली। एजेंसी

विमानन नियामक डीजीसीए ने मंगलवार को कहा कि उसने ग्रीष्मकालीन समयसारिणी के लिए 108 हवाई अड्डों से प्रति सप्ताह 18,843 उड़ानों को मंजूरी दी है। ग्रीष्मकालीन समयसारिणी मार्च के अंतिम रविवार से शुरू होती है और अक्टूबर के अंतिम रविवार तक चलती है। इस साल की ग्रीष्मकालीन समयसारिणी के लिए उड़ानों की संख्या को मंजूरी देते समय इस बात को ध्यान में रखा गया है कि विमानन कंपनियों को कोविड-पूर्व के मुकाबले 80 प्रतिशत से अधिक उड़ानों के संचालन की अनुमति नहीं है। नागर विमानन महानिदेशालय ने ट्वीट किया, ''गौरतलब है कि 108 हवाई अड्डों से प्रति सप्ताह 18,843 प्रस्थानों को अंतिम रूप दिया गया है। इन 108 हवाई अड्डों में बरेली, बिलासपुर, कुरनूल और रूपसी नए हवाई अड्डे हैं, जहां से विमान उड़ान भरेंगे।'' डीजीसीए ने कहा कि इनमें इंडिगो की 8,749 साप्ताहिक उड़ानें, स्पाइसजेट की 2,854 साप्ताहिक उड़ानें, गोएयर की 1,747 साप्ताहिक उड़ानें, एयर इंडिया की 1,683 साप्ताहिक उड़ानें, विस्तारा की 1,288 साप्ताहिक उड़ानें और एयरएशिया की 1,243 साप्ताहिक उड़ानें शामिल हैं।

कोविड-19 के दौरान भारत में 30 लाख लोगों ने डिजिटल कौशल हासिल किया : माइक्रोसॉफ्ट

नयी दिल्ली। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान उसने 249 देशों और क्षेत्रों के तीन करोड़ लोगों को डिजिटल कौशल हासिल करने में मदद की। इनमें 30 लाख लोग अकेले भारत से हैं। यह प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी द्वारा जून में घोषित 2.5 करोड़ के लक्ष्य से अधिक है। माइक्रोसॉफ्ट ने बयान में कहा कि कंपनी वैश्विक स्तर पर 2,50,000 कंपनियों को 2021 में कौशल आधारित नियुक्ति में मदद की प्रतिबद्धता को पूरा कर रही है। बयान में कहा गया है कि महामारी के दौरान बेरोजगार हुए कारखाना श्रमिकों, खुदरा क्षेत्र के सहायकों और ट्रक ड्राइवरों सहित लाखों लोग गिटहब, लिंक्डइन और माइक्रोसॉफ्ट के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का हिस्सा बन रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एशिया के अध्यक्ष अहमद मजहरी ने कहा, ''महामारी के बाद की दुनिया में कौशल नयी मुद्रा होगी। पिछले साल के दौरान हमने देखा है कि महामारी से दुनियाभर के लोग प्रभावित हुए। हमारा मानना है कि महामारी के बाद मजबूत होकर उबरने के लिए पुन:कौशल जरूरी है।''

ऑटोमेटिक पेमेंट के नए नियम लागू करने के लिए RBI ने बढ़ाई आखिरी तारीख

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑटोमेटिक भुगतान के लिए जो अतिरिक्त उपाय यानी एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (एएफए) 1 अप्रैल से अनिवार्य किया था, उसकी आखिरी तारीख अब बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दी गई है। रिजर्व बैंक ने ये तारीख इसलिए बढ़ाई है, ताकि ग्राहकों को किसी तरह की परेशानी ना हो। बैंक और भुगतान सुविधा प्रदान करने वाले तमाम प्लेटफॉर्म भी इसी बात की मांग कर रहे थे कि नए व्यवस्था को लागू करने के लिए उन्हें कुछ समय दिया जाए। अभी तक ये तारीख 31 मार्च 2021 थी, जिसके बाद ऑटोमेटिक भुगतान में परेशानियां आ सकती थीं। आरबीआई ने चार दिसंबर को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) तथा भुगतान सुविधा देने वाले मंचों समेत सभी बैंकों को निर्देश दिया था कि कार्ड या प्रीपेड भुगतान उत्पाद (पीपीआई) या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग कर स्वतः बिल भुगतान (घरेलू या विदेशी) की व्यवस्था में अगर एएफए का अनुपालन नहीं हो रहा है, तो वह व्यवस्था 31 मार्च, 2021 से जारी नहीं रहेगी।

क्या है रिजर्व बैंक के इस कदम का मकसद?

केंद्रीय बैंक ने जोखिम कम करने के उपायों के तहत इस कदम की घोषणा की जिसका मकसद कार्ड के जरिये लेन-देन को मजबूत और सुरक्षित बनाना है। अगर इस अतिरिक्त सत्यापन उपाय का अनुपालन नहीं किया गया, तो संबंधित इकाइयों को बिजली समेत अन्य ग्राहक केंद्रित सेवाओं, ओटीटी (ओवर द टॉप) समेत अन्य बिलों के भुगतान पर 30 सितंबर 2021 के बाद असर पड़ सकता है। हाल ही में आरबीआई ने संपर्क रहित कार्ड के जरिये भुगतान और कार्ड तथा यूपीआई के जरिये स्वतः बिलों के भुगतान की सीमा एक जनवरी से 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी। इस पहल का मकसद डिजिटल लेन-देन को सुगम और सुरक्षित बनाना है।

नए नियम के तहत बैंकों को करनें होंगे ये काम

इस नये नियम के तहत बैंकों को नियमित तौर पर बिलों के भुगतान के बारे में ग्राहक को सूचना देनी होगी और ग्राहक से मंजूरी के बाद ही उसका भुगतान किया जा सकेगा। अतः इससे बिलों का भुगतान स्वतः नहीं होगा, बल्कि ग्राहक से सत्यापन यानी मंजूरी के बाद ही हो सकेगा। नये दिशानिर्देश के तहत 5,000 रुपये से अधिक के भुगतान के लिये बैंकों को नये दिशानिर्देश के तहत ग्राहकों को 'वन-टाइम पासवर्ड' भेजना होगा। ई-वाणिज्य कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उद्योग अभी आरबीआई के निर्देश के क्रियान्वयन के लिये तैयार नहीं है। उसने कहा कि अगर आरबीआई ने नियम के अनुपालन को लेकर समय नहीं दिया तो एक अप्रैल से ग्राहक ने लेन-देन को लेकर जो ई- मंजूरी दे रखी है, बैंक उसका अनुपालन नहीं कर पाएंगे। इससे नियमित तौर पर बिलों के भुगतान और अन्य लेन-देन बाधित होंगे। इससे डिजिटल भुगतान को लेकर ग्राहकों का भरोसा टूटेगा।

अप्रैल में छुट्टियों की भरमार, जानें कब-कब बंद रहेंगे बैंक

आईपीटी नेटवर्क

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के अनुसार प्राइवेट और पब्लिक बैंक अप्रैल में 15 दिन बंद रहेंगे। इन 15 दिनों में 8 दिन त्यौहारों के कारण बैंक नहीं खुलेंगे, जबकि अन्य दिन रविवार और शनिवार की छुट्टियां रहेंगी। 1 अप्रैल को नए वित्तीय वर्ष के कारण बैंक में समान्य लेनदेन नहीं होंगे। जबकि दो अप्रैल को गुड फ्राइडे की छुट्टी रहेगी।

अप्रैल में छुट्टियों की भरमार

1 अप्रैल, गुरुवार - ओडिसा डे, बैंकों के सालाना अकाउंट्स का क्लोजिंग ईयर
2 अप्रैल, शुक्रवार - गुड फ्राइडे
4 अप्रैल, रविवार - ईस्टर (Easter)
5 अप्रैल, सोमवार - बाबू जगजीवन राम जयंती
10 अप्रैल सेकेंड सैटरडे
11 अप्रैल रविवार
13 अप्रैल, मंगलवार - उगड़ी, तेलुगू न्यू ईयर, गुड़ी पाड़वा, वैसाख, बिजू फेस्टिवल, बोहाग बिहू
14 अप्रैल, बुधवार - डॉ. अंबेडकर जयंती, तमिल न्यू ईयर, अशोकी महान की जयंती।
15 अप्रैल, गुरुवार - हिमाचल डे, विशु, बंगाली न्यू ईयर, सरहुल
18 अप्रैल, रविवार
21 अप्रैल, गुरुवार - रामनवमी
24 अप्रैल चौथा शनिवार
25 अप्रैल, रविवार - महावीर जयंती

डीडी फ्री डिश के ग्राहकों की संख्या चार करोड़ के पार : रिपोर्ट

नई दिल्ली। एजेंसी

सरकारी प्रसारक प्रसार भारती की डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सेवा डीडी फ्री डिश के ग्राहकों की संख्या चार करोड़ को पार कर गई है।एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। ईवाई फिक्की की मीडिया एंटरटेनमेंट रिपोर्ट-2021 में कहा गया है कि प्रसार भारती की बहु-चैनल फ्री-टू-एयर डीटीएच सेवा के दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी की मुख्य वजह टेलीविजन सेट सस्ते होना, आर्थिक मुद्दे और डीटी रेट्रो चैनल शुरू होना तथा बड़े प्रसारकों का फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर लौटना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डीडी फ्री डिश मजबूत वृद्धि की राह पर है। इसके ग्राहकों की संख्या चार करोड़ को पार कर गई है। एक बयान में कहा गया है कि 2025 तक टीवी सेट वाले परिवारों की संख्या पांच प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। इसमें कनेक्टेड टीवी का प्रमुख योगदान होगा, जिसकी संख्या 2025 तक चार करोड़ हो जाएगी। डीडी फ्री डिश के ग्राहकों की संख्या पांच करोड़ को पार कर जाएगी। डीडी फ्री डिश का मुख्य उद्देश्य लोगों को बिना किसी शुल्क के गुणवत्ता वाले मनोरंजन और सूचना का एक वैकल्पिक व सस्ता मंच उपलब्ध कराना है। फिलहाल डीडी फ्री डिश 161 चैनल दिखाता है। इसमें से 91 दूरदर्शन चैनल हैं।

अभी लागू नहीं होंगे लेबर कोड के नियम, कंपनियों को मिली राहत

नई दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने 1 अप्रैल से लेबर कोड नियमों को लागू करने के फैसला टाल दिया है। राज्य सरकारों के नियमों को अभी फाइनल नहीं किया जिसके कारण इन्हें टाला गया है। लेबर कोड टालने का फैसला इसलिए भी लिया गया ताकि कंपनियों को सैलरी स्ट्रक्चर और एचआर पॉलिसी बदलने के लिए समय मिल जाए क्योंकि इन नियमों के कंपनियों की कर्मचारी लागत बढ़ जाएगी।

सीनियर श्रम मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक लेबर कोड को कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। सीनियर श्रम मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक लेबर कोड को कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। सरकार चाहती है कि केंद्र के साथ कम से कम कुछ औद्योगिक राज्य लेबर कोड के नियमों को नोटिफाई करें। ताकि, कोई भी कानूनी परेशानी न हो। श्रम मंत्रालय लेबर कोड के चार नियमों के साथ तैयार हैं। जब कुछ राज्य इन्हें लागू करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो इन्हें नोटिफाई कर देगी। जम्मू और कश्मीर ने नियमों को नोटिफाई किया है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश ने दो कोड्स को ड्राफ्ट किया है। कर्नाटक एक कोड को मानने के लिए तैयार है।

लेबर कोड नियमों के टलने से भारतीय उद्योग जगत को राहत मिली है क्योंकि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच औद्योगिक राज्यों ने आशंका जताई थी। कोरोना के बढ़ते मामलों से इकोनॉमिक रिकवरी पर असर पड़ सकता और अगर आगे ऐसे ही मामले बढ़ते रहे तो हालात और खराब हो सकते हैं।

श्रम मंत्रालय ने 29 लेबर कानूनों का एकीकरण कर चार कर दिया है। ताकि, पेपर वर्क कम हो, कारोबार करना आसान हो, वर्कर्स को रखना और निकालना आसान हो और काम के घंटों में लचीलापन आ सके। पिछले साल संसद में मजदूरी संहिता विधेयक (कोड ऑन वेजेज बिल) पास किए गए थे।

लेबर कोड के नियम

नए ड्राफ्ट रूल के अनुसार, मूल वेतन कुल वेतन का 50इ या अधिक होना चाहिए। इससे ज्यादातर कर्मचारियों का वेतन संरचना बदलेगा, क्योंकि वेतन का गैर-भत्ते वाला हिस्सा आमतौर पर कुल सैलेरी के 50 फीसदी से कम होता है। वहीं कुल वेतन में भत्तों का हिस्सा और भी अधिक हो जाता है। मूल वेतन बढ़ने से आपका पीएफ भी बढ़ेगा। पीएफ मूल वेतन पर आधारित होता है। मूल वेतन बढ़ने से पीएफ बढ़ेगा, जिसका मतलब है कि टेक-होम या हाथ में आने वाला वेतन में कटौती होगी।

ट्राई ने थोक एसएमएस के नये नियमों के अनुपालन के लिये प्रमुख मंत्रालयों, संगठनों को पत्र लिखा

नई दिल्ली। एजेंसी

दूरसंचार नियामक ट्राई ने प्रमुख मंत्रालयों, सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) और नॉस्कॉम तथा एनआईसी जैसे संगठनों और नोडल एजेंसियों को थोक में भेजे वाले एसएमएस के संदर्भ में 31 मार्च के बाद नये नियमों का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को लेकर पत्र लिखा है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) से जुड़े सूत्रों ने बताया कि एनआईसी ने नियामक को आश्वस्त किया है कि वाणिज्यिक संदेशों के लिये नये नियम लागू होने को लेकर सरकारी संगठनों की मदद करने तथा उससे जुड़े किसी भी समस्या के समाधान के लिये वह पूरी तरह से तैयार है। नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) सरकारी कामकाज को लेकर प्रौद्योगिकी सहायता उपलब्ध कराता है।

नियामक ने विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित पक्षों को पत्र लिखकर उन्हें नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है और उनसे अपने मातहत आने वाली इकाइयों तथा संगठनों से नये नियमन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह देने को कहा है। नये नियम के बारे में लोगों को जागरूक करने के अपने अभियान के तहत ट्राई ने उद्योग मंडलों सीआईआई, फिक्की, एसोचैम, नॉस्कॉम और सीओएआई से आग्रह किया है कि वे नयी नियामकीय आवश्यकताओं के बारे में अपने सदस्यों को जानकारी दें।

एनआईसी, सीडैक के अलावा पत्र उन सरकारी संगठनों को भी लिखा गया है जो रियायती एसएमएस का लाभ उठा रहे हैं।

इससे पहले भी नियामक केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रालयों तथा मुख्य सचिवों को इस बारे में अवगत करा चुका है। ट्राई का व्यावसायिक संदेशों (एसएमएस) के लिये नियम 'ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकी' पर आधारित है। इसका मकसद अवांछित और धोखाधड़ी के इरादे से भेजे गये संदेशों पर लगाम लगाना है।

नये नियम के तहत यह जरूरी है कि जो पात्र इकाइयां व्यावसायिक संदेश भेज रही हैं, वे संदेश भेजने वाले, सॉफ्टवेयर आदि (मैसेज हेडर) तथा टेम्पलेट (पहले से तैयार संदेश) के बारे में दूरसंचार परिचालकों के पास पंजीकरण कराएं।

जब बैंक, भुगतान कंपनियां या अन्य उपयोगकर्ता एसएमएस और ओटीपी भेजते हैं, उनकी जांच ब्लॉकचैन मंच पर पंजीकृत टेम्पलेट से की जाती है। इस प्रक्रिया को 'एसएमएस स्क्रबिंग' कहते हैं यानी संदेश उसी तरीके से व्यक्तियों को मिले जिसके लिये उसने निर्धारण कर रखा है। 'टेम्पलेट' के पंजीकरण तथा अन्य विभिन्न प्रकार की जांच प्रक्रिया से संदेश भेजने वाले सही इकाइयों की पहचान तथा संदेश भेजने के मकसद का सत्यापन हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि इस महीने की शुरुआत में एसएमएस और ओटीपी वन टाइम पासवर्ड भेजे जाने से संबद्ध बैंक, क्रेडिट कार्ड भुगतान और कुछ अन्य सेवाओं के मामले में समस्या उत्पन्न हुई। यह समस्या तब उत्पन्न हुई जब दूरसंचार कंपनियों ने ट्राई के नये नियम का क्रियान्वयन किया। इसका कारण मूल इकाइयों (थोक में और व्यावसायिक संदेश भेजने वाले) द्वारा इस दिशा में उपयुक्त कदम नहीं उठाया जाना था।

इस प्रकार की बाधाओं को देखते हुए ट्राई ने ऐसी कंपनियों को अस्थायी तौर पर राहत दी लेकिन उन्हें नियमों के अनुपालन को लेकर तत्काल कदम उठाने को कहा। दूरसंचार नियामक ने पिछले शुक्रवार को 40 चूककर्ता मूल इकाइयों की सूची जारी की जिन्होंने थोक व्यावसायिक संदेशों को लेकर उसके नियमन को पूरा नहीं किया। इन इकाइयों में एचडीएफसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसी इकाइयां शामिल हैं। ट्राई ने इस मामले में अपना रुख कड़ा करते हुए चूक करने वाली इकाइयों को आगाह करते हुए कहा है कि वे नये नियमों के अनुपालन को लेकर 31 मार्च 2021, तक निर्धारित जरूरतों को पूरा करें ताकि एक अप्रैल, 2021 से ग्राहकों के साथ संवाद एसएमएस के जरिये को लेकर कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो।

दिल्ली-मुंबई राजमार्ग बनेगा 'ई-राजमार्ग', सामान के परिवहन की लागत हो जाएगी 70% कम

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि शहरी इलाकों से गुजरने वाली सड़कों पर फुटपाथ और साइकिल ट्रैक बनाए जाएंगे। लोकसभा में मनीष तिवारी, भोला सिंह और कुछ अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में गडकरी ने यह भी बताया कि दिल्ली-मुंबई राजमार्ग को 'ई-राजमार्ग' बनाया जाएगा, जिससे इस राजमार्ग पर परिवहन सेवाएं सस्ती पड़ेंगी और साजो-सामान के परिवहन संबंधी सेवाओं पर लागत 70 फीसदी कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में शहरों से निकलने वाले मार्गों पर फुटपाथ और साइकिल ट्रैक बनाए जाएंगे। गडकरी ने सांसदों का आह्वान किया कि वे ई-साइकिल (इलेक्ट्रिक) को लोकप्रिय बनाएं। उन्होंने कहा, "देश में आबादी और वाहनों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। यह एक समस्या है.... हमें नई-नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना होगा। यह सस्ता भी पड़ेगा और उपभोक्ता के हित में भी होगा।"

गडकरी से नाराज हैं आरटीओ!

मंत्री ने ड्राइविंग लाइसेंस और परिवहन संबंधी कई अन्य कागजात के ऑनलाइन बनाए जाने का उल्लेख करते हुए कहा, "आरटीओ मुझसे नाराज हैं...अब आरटीओ कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है।" टोल पर लगने वाले जाम का हवाला देते हुए गडकरी ने कहा, "फास्टैग प्रणाली लागू होने के बाद कई टोल पर जाम कम हो गया है। हमने सुनिश्चित किया है कि टोल पर तीन मिनट से ज्यादा नहीं रुकना पड़े। कोविड और किसान आंदोलन के बावजूद टोल के जरिए होने वाली आमदनी बढ़ गई है।"

क्या है गिग अर्थव्यवस्था, जिससे 9 करोड़ रोजगार सृजन में मिल सकती है मदद

मुंबई। एजेंसी

गिग अर्थव्यवस्था (Gig Economy) से गैर-कृषि क्षेत्रों में 9 करोड़ रोजगार सृजन में मदद मिल सकती है। गिग अर्थव्यवस्था यानी कुछ समय के लिए नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों की व्यवस्था। साथ ही इससे दीर्घकाल में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 1.25 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है। परामर्श कंपनी बीसीजी की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। गिग अर्थव्यवस्था से आशय रोजगार की ऐसी व्यवस्था से है, जहां स्थायी तौर पर कर्मचारियों को रखे जाने के बजाए अल्प अवधि के लिए अनुबंध पर रखा जाता है। रिपोर्ट के अनुसार गिग अर्थव्यवस्था कोई नई धारणा नहीं है। बल्कि प्रौद्योगिकी के साथ इसे तेजी से अपनाया जा रहा है। कुछ साल पहले जब बिना रोजगार सृजन के वृद्धि की बात कही जा रही थी, सरकार ने अस्थायी तौर पर सृजित होने वाले रोजगार यानी गिग अर्थव्यवस्था रोजगार की बात कही थी। इसमें कहा गया है कि अल्पावधि से दीर्घावधि में कुशल, कम कुशल और साझा सेवा के क्षेत्र में करीब 2.4 करोड़ रोजगार सृजित हो सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक 7 करोड़ अस्थायी नौकरियां निर्माण, विनिर्माण, परिवहन और लॉजिस्टक व व्यक्तिगत सेवा क्षेत्रों में हैं।

600 से अधिक शहरी परिवार के बीच सर्वे

परामर्श कंपनी के अनुसार उसका अनुमान विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के प्रकार का विस्तृत अध्ययन पर आधारित है। यह निष्कर्ष बड़ी और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों समेत विभिन्न कंपनियों से बातचीत के आधार पर निकाला गया है। इसको लेकर 600 से अधिक शहरी परिवार के बीच सर्वे किया गया और उद्योग विशेषज्ञों की राय ली गई।

कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धि के प्रयोग हेतु नीति, वित्तीय समर्थन की आवश्यकताः नास्कॉम

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

आईटी उद्योग निकाय नास्कॉम ने कहा कि भारत को कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धि (एआई) की पूर्ण संभावनाओं का फायदा लेने के लिए नीतिगत और वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। देश का कृषि क्षेत्र अभी भी कई चुनौतियों का सामना करता है। इसने कहा है कि एआई में कृषि क्षेत्र को कठिन लागत परिस्थितियों से मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता है, जो आंकड़ा-संचालित खेती की ओर एक बदलाव को उत्प्रेरित करता है।

इसमें कहा गया है कि सटीक कृषि और कृषि प्रबंधन, कृषि रोबोट, स्वचालित निराई, फसल की गुणवत्ता और उसके तैयार होने की पहचान, कीट भविष्यवाणी एवं उसकी रोकथाम, पशुधन की निगरानी एवं प्रबंधन, फसल उपज का आकलन, आदि जैसे कई एआई उपयोग वाले मामले, एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला और बुद्धिमान खेत संचालन के माध्यम से परिचालन दक्षता में सुधार लाते हुए कृषि उत्पादकता में सुधार लाकर और किसानों को सशक्त बना सकते हैं।

अर्नस्ट एंड यंग (ईवाई) के साथ मिलकर 'भारत के कृषि उत्पादन को अधिकतम करने के लिए एआई का उपयोग' रिपोर्ट के अनावरण के मौके पर, नास्कॉम के अध्यक्ष देबजानी घोष ने कहा कि नीदरलैंड की तरह, भारत भी कृषि क्षेत्र में एआई प्रौद्योगिकियों की क्षमता का उपयोग कर सकता है। घोष ने एक बयान में कहा, "नीदरलैंड कृषि में प्रभावी एआई अपनाने का एक शानदार उदाहरण है। महज एक छोटी कृषि योग्य भूमि के साथ वह देश, दुनिया के कृषि उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है।" घोष ने कहा कि एआई की पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए, आवश्यक बुनियादी ढांचा और नीति सहायता प्रदान करने के लिए सरकार, उद्योगों, और स्टार्ट-अप का गठबंधन, विभिन्न क्षेत्रों में एआई नवाचार को लागू करना तथा स्टार्टअप का संरक्षण और उसे वित्तीय सहायता प्रदान करना अनिवार्य हैं। मौजूदा समय में, कई एआई के क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्ट-अप अभिनव एआई नीत समाधान विकसित कर रहे हैं, जो मूल्य श्रृंखला में विशिष्ट चुनौतियों को लक्षित करते हैं। सटीक खेती, फसल रोग प्रबंधन और उपज छँटाई और ग्रेडिंग स्टार्ट-अप के लिए शीर्ष प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं।

शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 20 पैसे टूटा

मुंबई। एजेंसी

अमेरिकी डॉलर की मजबूती और घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली के चलते भारतीय रुपया बुधवार को डॉलर के मुकाबले 20 पैसे टूटकर 73.58 के स्तर पर आ गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में घरेलू इकाई अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 73.56 पर खुली और आगे गिरावट दर्ज करते हुए 73.58 के स्तर पर आ गई, जो पिछले बंद के मुकाबले 20 पैसे की गिरावट दर्शाता है। रुपया मंगलवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 73.38 पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.13 प्रतिशत बढ़कर 93.41पर पहुंच गया। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा 0.48 प्रतिशत बढ़कर 64.45 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

1 अप्रैल से बोतलबंद पानी बेचना नहीं होगा आसान, कंपनियों को करना होगा यह काम

नई दिल्ली।एजेंसी

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने बोतलबंद पानी और मिनरल वॉटर विनिर्माताओं के लिए लाइसेंस हासिल करने या पंजीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों को भेजे पत्र में एफएसएसएआई ने यह निर्देश दिया है। यह निर्देश एक अप्रैल, 2021 से लागू होगा। एफएसएसएआई ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2008 के तहत सभी खाद्य कारोबार परिचालकों (एफबीओ) के लिए किसी खाद्य कारोबार को शुरू करने से पहले लाइसेंस/पंजीकरण हासिल करना अनिवार्य होगा। नियामक ने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रतिबंध एवं बिक्री पर अंकुश) नियमन, 2011 के तहत कोई भी व्यक्ति बीआईएस प्रमाणन चिन्ह के बाद ही बोतलबंद पेयजल या मिनरल वॉटर की बिक्री कर सकता है।

रिन्यूवल के लिए भी अनिवार्य होगा बीआईएस लाइसेंस

एफएसएसएआई ने कहा कि पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर बनाने वाली कई कंपनियां एफएसएसएआई के लाइसेंस पर काम कर रही हैं लेकिन उनके पास बीआईएस सर्टिफिकेशन मार्क नहीं है। इसे देखते एफएसएसएआई के लाइसेंस के लिए बीआईएस लाइसेंस या इसके लिए आवेदन को अनिवार्य बना दिया गया है। एफएसएसएआई लाइसेंस के रिन्यूवल के लिए भी बीआईएस लाइसेंस अनिवार्य होगा।

कोल इंडिया का 2020-21 में उत्पादन घटने का अनुमान, 60 करोड़ टन से नीचे रहेगा

कोलकाता। एजेंसी

दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी कोल इंडिया लि. (सीआईएल) के उत्पादन में चालू वित्त वर्ष 2020-21 में 50 से 60 लाख टन की मामूली गिरावट आ सकती है। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष में कोल इंडिया का उत्पादन 60 करोड़ टन से काफी नीचे रहेगा। वित्त वर्ष 2019-20 में कंपनी का कोयला उत्पादन 60.2 करोड़ टन रहा था। वहीं 2018-19 में कोल इंडिया ने 60.69 करोड़ टन का अपना सबसे ऊंचा उत्पादन दर्ज किया था। यह लगातार दूसरा साल होगा जबकि कोल इंडिया का उत्पादन घटेगा। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में 66 करोड़ टन उत्पादन का लक्ष्य रखा था। साल के मध्य में कंपनी ने उम्मीद जताई थी कि उसका उत्पादन 63 से 64 करोड़ टन रहेगा। अधिकारियों ने कहा कि कोविड-19 की वजह से पैदा हुई अड़चनों के चलते कोल इंडिया का उत्पादन प्रभावित हुआ है। महामारी की वजह से मांग घटी है जिसकी वजह से कंपनी के पास कोयले का भंडार जमा हो गया है और उसे अपने उत्पादन में कटौती करनी पड़ी है। सूत्रों ने कहा कि 27 मार्च तक कोल इंडिया का उत्पादन 58.5 करोड़ टन रहा है। माह के शेष दिनों में 1.1 करोड़ टन का और उत्पादन होगा। इस तरह कंपनी का कुल उत्पादन 59.6 से 59.7 करोड़ टन के बीच रहेगा। वित्त वर्ष के दौरान कोयले का उठाव 57.7 करोड़ टन रहने की उम्मीद है। कोल इंडिया के पास कोयले का भंडार फरवरी के अंत तक बढ़कर 7.78 करोड़ टन हो गया है। जनवरी के अंत तक यह 6.68 करोड़ टन था।

फिर बढ़ी DL, RC, परमिट जैसे व्हीकल डॉक्युमेंट की वैधता अवधि, अब इस तारीख तक रहेंगे वैलिड

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरकार ने शुक्रवार को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को भेजे एक परामर्श में कहा है कि वह फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा रहा है, जिनका लॉकडाउन के कारण विस्तार नहीं किया जा सकता है और जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को खत्म हो गई है या 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाएगी। इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को कई बार बढ़ाया जा चुका है। मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि यह सलाह दी जाती है कि एक फरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 जून, 2021 तक वैध मानी जा सकती है। परामर्श में कहा गया कि संबंधित अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 जून 2021 तक वैध मानें।

भारत का वार्षिक सकल घरेलु उत्पाद 2021 में 2019 से कम रहने के असार: संरा रिपोर्ट

नयी दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी पर लगाम लगाने के लिये टीकाकरण की शुरूआत के बावजूद भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2021 में 2019 के स्तर से नीचे रहने के आसार हैं। यह बात एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी) की मंगलवार को जारी एक एक रिपोर्ट में कही गयी है। 'एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिये आर्थिक और सामाजिक सर्वे, 2021: कोविड-19 बाद मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर' शीर्षक से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2021-22 में 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है जबकि चालू वित्त वर्ष (2020-21) में महामारी और सामान्य कारोबारी गतिविधियों पर उसके प्रभाव के कारण इसमें 7.7 प्रतिशत से अधिक गिरावट होने का अनुमान है। रिपार्ट में कहा गया है कि भारत में महामारी का प्रकाप शुरू होने से पहले जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) और निवेश धीमा पड़ चुका था। "कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये भारत में जो लॉकडाउन लगाया गया, वह दुनिया में लगाए गए सबसे कड़े 'लॉकडाउन' में से एक था। उसके कारण 2020 की दूसरी तिमाही (अप्रैल-जून) में आर्थिक बाधाएं अपने चरम पर थी।" संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार बाद में लॉकडाउन नीतियों में बदलाव और संक्रमण दर में कमी से तीसरी तिमाही से आर्थिक पुनरूद्धार को गति मिली।

हालांकि सालाना आधार पर शून्य के करीब वृद्धि दर के अनुमान के साथ चौथी तिमाही में पुनरूद्धार की

गति हल्की पड़ी। रिपोर्ट के अनुसार, "कोविड-19 मामलों में अच्छी-खासी कमी तथा टीकाकरण शुरू होने के बावजूद 2021 मेंभारत का आर्थिक उत्पादन (जीडीपी) 2019 के स्तर से नीचे रहने का अनुमान है।" इसमें कहा गया है कि देय के सामने कर्ज की लागत नीचे रखने के साथ गैर-निष्पादित कर्ज यानी फंसे कर्ज की समस्या को काबू में रखना भी चुनौती होगी।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय(एनएसओ) के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2020-21 में भारत की वृद्धि दर में 8 प्रतिशत की गिरावट आएगी। यह महामारी के प्रभाव को बताता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन ने कोविड-19 से निपटने के लिये तुरंत और प्रभावी कदम उठाए। इससे वह दुनिया में एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है जो 2020 में सकारात्मक वृद्धि दर हासिल करने में सक्षम हो पाया। औद्योगिक उत्पादन, बुनियादी ढांचा और आवास निवेश में मजबूत पुनरूद्धार तथा निजी खपत में कुछ सुधार से चौथी तिमाही में उसकी वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रही जो महामारी पूर्व वृद्धि के स्तर से अधिक है। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि विकासशील एशिया-प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर औसतन 2021 में 5.9 प्रतिशत जबकि 2022 में 5 प्रतिशत रहेगी। वहीं 2020 में एक प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है। इसमें कहा गया है कि 2021 में मजबूत पुनरूद्धार की उम्मीद के बावजूद आर्थिक स्थिति में सुधार की दर उतार चढ़ाव भरी रहने की संभावना है। इसमें महामारी के बाद पुनरूद्धार में गरीब देश और वंचित तबके के लोग सबसे ज्यादा ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। रिपोर्ट में मजबूत और समावेशी पुनरूद्धार के लिये विभिन्न देशों में कोविड-19 टीकाकरण में अधिक समन्वय तथा क्षेत्रीय सहयोग की जरूरत पर बल दिया गया है। इसमें सिफारिश की गयी है कि अर्थव्यवस्थाओं को राजकोषीय और मौद्रिक समर्थन जारी रखा जाना चाहिए क्योंकि समय से पहले इन कदमों को वापस लेने से दीर्घकालीन समस्याएं बढ़ सकती हैं।

क्यों मनाई जाती है रंगपंचमी

रंगों का यह त्योहार प्रमुख रूप से 5 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन होलिका को जलाया जाता है, जिसे होलिका दहन कहते हैं। दूसरे दिन लोग एक-दुसरे को रंग व अबीर-गुलाब लगाते हैं जिसे धुरड्डी व धूलिवंदन कहा जाता है। होली के पांचवें दिन रंगपंचमी को भी रंगों का उत्सव मनाते हैं। 28 मार्च को होलिका दहन था, 29 मार्च को धुलेंडी और अब 2 अप्रैल 2021 को रंगपंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। आओ जानने हैं कि रंग पंचमी क्यों मनाई जाती है।

1. चैत्रमास की कृष्णपक्ष की पंचमी को खेली जाने वाली रंगपंचमी देवी देवताओं को समर्पित होती है। मान्यता है कि रंगपंचमी पर पवित्र मन से पूजा पाठ करने से देवी देवता स्वयं अपने भक्तों को आशीर्वाद देने आते हैं और कुंडली के बड़े से बड़े दोष को इस दिन पूजा पाठ से दूर किया जा सकता है।
2. कहते हैं कि इस दिन श्री कृष्ण ने राधा पर रंग डाला था। इसी की याद में रंग पंचमी मनाई जाती है। इस दिन श्री राधारानी और श्रीकृष्ण की आराधना की जाती है। रंगपंचमी में होली की तरह रंग खेले जाते हैं। इसमें राधा कृष्ण जी को भी अबीर गुलाल लगाया जाता है। राधारानी के बरसाने में इस दिन उनके मंदिर में विशेष पूजा और दर्शन लाभ होते हैं।
3. मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि, इस दिन हवा में रंग और अबीर उड़ाने से वातावरण में सकारात्मकता का संचार होता है जिसका प्रभाव व्यक्ति के मन मस्तिष्क और जीवन पर पड़ता है। साथ ही इससे लोगों के बुरे कर्म और पाप आदि नष्ट हो जाते हैं।
4. यह भी कहते हैं कि यह सात्विक पूजा आराधना का दिन होता है। रंगपंचमी को धनदायक भी माना जाता है।
5. यह भी कहा जाता है कि श्रीकृष्ण ने गोपियों के संग रासलीला रचाई थी और दूसरे दिन रंग खेलने का उत्सव मनाया था। इसके अलावा इस दिन शोभा यात्राएं भी निकाली जाती है और होली की तरह देव होली के दिन भी लोग एक दूसरे पर रंग और अबीर डालते हैं।
6. गोवा और महाराष्ट्र में रंग पंचमी के दिन मछुआरों की बस्ती में खास आयोजन होता है। सबके लिए नाच-गाने से लेकर खाने-पीने तक के बंदोबस्त किए जाते हैं। इस दिन मछुआरे एक-दूसरे के घर पर मिलने जाते हैं और शादी तय करने के लिए इस दिन को सर्वोत्तम मानते हैं।

रंग पंचमी पर विशेष

इस दिन एक-दूसरे को छू कर नहीं बल्कि, हवा में रंग उड़ाकर मनाना चाहिए ये पर्व

रंगपंचमी पर हवा में उड़ाए रंगों का मतलब है देव तत्व की पूजा, इस दिन रंग उड़ाकर देवताओं का स्वागत करना चाहिए

होली के बाद चैत्र महीने के कृष्णपक्ष की पांचवी तिथि को रंग पंचमी पर्व मनाया जाता है। पौराणिक परंपरा के मुताबिक इस दिन आसमान में रंग उड़ाकर देवताओं का स्वागत करना चाहिए। इससे देवी-देवता भी प्रसन्न होते हैं। रंग पंचमी को अनिष्टकारी शक्तियों पर जीत हासिल करने वाला त्योहार माना जाता है। इस बार ये उत्सव 2 अप्रैल को मनाया जाएगा।

इस पर्व के लिए ये भी कहा जाता है कि इस दिन श्रीकृष्ण ने राधाजी पर रंग डाला था। इसी याद में रंग पंचमी मनाई जाती है। इस दिन राधारानी और श्रीकृष्ण की आराधना की जाती है। राधारानी के बरसाने में इस दिन उनके मंदिर में विशेष पूजा और दर्शन लाभ होते हैं। ये भी कहा जाता है कि इस दिन श्रीकृष्ण ने गोपियों संग रासलीला की थी और दूसरे दिन रंग खेलने का उत्सव मनाया था।

राधा-कृष्ण को चढ़ाया जाता है अबीर-गुलाल

ये त्योहार खासतौर से मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार को बड़ी धूमधाम के साथ अबीर और गुलाल के रंगों को बिखेरते हुए मनाया जाता है। इसमें राधा-कृष्ण को भी अबीर और गुलाल चढ़ाया जाता है। कई जगह शोभायात्रा भी निकलती है, जिसमें लोग एक-दूसरे पर अबीर-गुलाल डालते हैं और हवा में उड़ाते हैं।

देवताओं का स्वागत

रंग पंचमी पर एक-दूसरे को छू कर रंग लगाकर नहीं बल्कि हवा में खुशी से रंगों को उड़ाकर मनाना चाहिए। ऐसा करके रंगों के जरीये से देवताओं का आह्वान किया जाता है। ऐसा करते समय ये भाव रखना चाहिए कि हम देवताओं का स्वागत करने के लिए रंगकणों को बिछा रहे हैं। इस दिन धरती के चारों ओर मौजूद नकारात्मक ताकतों पर दैवीय शक्ति का असर ज्यादा होता है। रंग पंचमी पर उड़ाए गए रंगों से इकट्ठा हुए शक्ति के कण बुरी ताकतों को कमजोर करते हैं। वायुमंडल में रंग उड़ाना यानी ब्रह्मांड में मौजूद देवता तत्व की पूजा करना है।

सात देवताओं के सात रंग

इस दिन होली की तरह रंग खेले जाते हैं। यह दिन देवताओं को समर्पित माना जाता है। ब्रह्मांड में मौजूद गणपति, श्रीराम, हनुमान, शिव, श्रीदुर्गा, दत्त भगवान एवं कृष्ण ये सात देवता सात रंगों से जुड़े हैं। उसी तरह इंसान के शरीर में मौजूद कुंडलिनी के सात चक्र सात रंगों और सात देवताओं से संबंधित हैं। रंग पंचमी मनाने का मतलब है रंगों की मदद से सातों देवताओं को जागृत कर खुद को उनसे जोड़ना।

सेहत के लिए चैत्र मासः 27 अप्रैल तक रहेगा ये महीना

इस दौरान खान-पान में बदलाव से बढ़ती है रोग प्रतिरोधक क्षमता

हिंदू कैलेंडर का पहला महीना यानी चैत्र मास, 29 मार्च से शुरू हो गया है, जो कि 27 अप्रैल तक रहेगा। इस महीने के दौरान वसंत ऋतु भी होती है। इसलिए इसे मधुमास भी कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्द्ध में सूर्य आसमान में ज्यादा देर तक रहता है। साथ ही सूर्य अपनी उच्च राशि में रहता है। इससे सूर्य का प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। चैत्र महीने के दौरान खान-पान और दिनचर्या में बदलाव किए जाते हैं। जिससे बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है और पूरे साल सेहत अच्छी रहती है।

उगते सूरज को जल चढ़ाना

चैत्र महीने के दौरान सूर्योदय से पहले उठकर नहाना चाहिए। सूर्य नमस्कार करना चाहिए। साथ ही उगते हुए सूरज को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को भगवान विष्णु का ही रूप माना गया है। इसलिए वसंत ऋतु में जब सूर्य की किरणें सृजन करती हैं, तब सूरज को जल चढ़ाने से जीवनी शक्ति तो बढ़ती ही है साथ ही बीमारियों से लड़ने की ताकत और उम्र भी बढ़ती है।

नहीं खाना चाहिए नया अनाज

चैत्र महीने के दौरान वसंत ऋतु रहती है। आयुर्वेद में इस कहा गया है कि इस ऋतु के दौरान नए अनाज और नया चावल नहीं खाना चाहिए। बल्कि भोजन में जौ, ज्वार और पुराना अनाज शामिल करना चाहिए। इस महीने में जो तीज-त्योहार आते हैं उनकी परंपराएं के मुताबिक नए अनाज और नए चावल देवी-देवताओं को चढ़ाते हैं। होलिका दहन में भी मौसम के पहले गेहूं की बालियां जलाई जाती हैं।

एक समय भोजन

चैत्र महीने के दौरान एक समय खाना खाना चाहिए। साथ ही नमक का त्याग भी करना चाहिए। ये भी एक तरह का व्रत ही होता है। ऐसा करने से शरीर में बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। चैत्र में एक समय खाना खाने के साथ ही फलों का सेवन भी ज्यादा करना चाहिए। इस महीने व्रत के दौरान गुनगुना पानी पीना चाहिए। इससे शिशिर ऋतु के दौरान शरीर में बना कफ धीरे-धीरे खत्म होने लगता है।

इस तरह के खाने से करें परहेज

चैत्र महीने में ज्यादा तला-गला और मसालेदार खाने से दूरी रखनी चाहिए। इस समय ऋतुओं का संक्रमण होता है जिससे इस दौरान पाचन शक्ति पर भी असर पड़ता है। ऐसे में चैत्र महीने में ज्यादा तैलीय और मसालेदार भोजन से परहेज रखने का विधान ग्रंथों में बताया गया है।

राजयोग भोगते हैं ऐसे लोग

आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी। हाथ में राजयोग लिखवा कर लाया है। इसका मतलब है जिन लोगों के हाथों में यह योग होता है वह बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। ज्योतिष विज्ञान में राजयोग को बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। राजयोग यानी राजा जैसा योग जिसमें सभी सुख-सुविधाएं, ऐश्वर्य और धन-धान्य हो। जिनके पास ऐसा होता है वे किसी राजा से कम भी नहीं होते। लेकिन सवाल यह है कि राजयोग होता क्या है। जानिए हाथ में बनने वाले राजयोग के बारे में। ऐसे लोग जिनके हथेली के बीच में घोड़ा यानी अश्व, घड़ा, पेड़ या स्तंभ का निशान होता है तो वह राजयोग भोगता है। ऐसे लोग बेहद धनवान होते हैं। इसी तरह जिन लोगों का मस्तक यानी ललाट चौड़ा हो, विशाल हो, नेत्र सुंदर हों, मस्तक गोलाई लिए हो और भुजाएं लंबी तो ऐसा व्यक्ति भी राजसुख भोगता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के हाथों में धनुष, चक्र, माला, कमल, ध्वजा, आसन, रथ अथवा चतुष्कोण हो तो इन लोगों पर भी लक्ष्मी की कृपा रहती है। इन लोगों को सब सुख-सुविधाएं मिलती हैं। इसी तरह यदि अंगूठे में यव का निशान मौजूद हो, मछली, छात्रा, अंकुश, वीणा, सरोवर या फिर हाथी समान कोई निशान बना हो तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक यश को पाने वाला और अकूत धन का स्वामी होता है। ऐसे लोग जिनके हाथों में सूर्य की रेखा मस्तक रेखा से मिल हो, मस्तक रेखा साफ और सीधी होकर गुरु पर्वत की ओर झुकते हुए चतुष्कोण का निर्माण कर रही हो ऐसा व्यक्ति मंत्री पद का सुख भोगता है। हाथों में गुरु एवं सूर्य पर्वत उच्च हों, शनि एवं बुध रेखा पुष्ट और स्पष्ट हो तो ऐसा व्यक्ति शासन में उच्च पद को पाने वाला होता है।

इन राशियों के लोगों को नहीं लगता किसी से डर

हर किसी का स्वभाव अलग-अलग होता है। इसके पीछे का कारण इनकी राशि पर पड़े असर के कारण होता है। ऐसे में ही कुछ लोग बेहद ही चंचल व डरपोक होते हैं। वहीं इसके विपरित कुछ राशि के लोग बेहद ही शक्तिशाली व आत्मविश्वासी होते हैं। ये हर काम को दिमाग व दिल दोनों से सोच कर करते हैं।ऐसे में इन राशि के लोगों को बाहुबली कहना गलत ना होगा। तो चलिए आज हम आपको ऐसी 4 राशियों के बारे में बताते हैं, जो बेहद ही निडर होते हैं। साथ ही जीवन में हर काम में सफलता हासिल करते हैं।

मेष राशि- इस राशि के लोगों की कुंडली में मंगल व सूर्य मजबूत होता है। ऐसे में ये बेहद ही आत्मविश्वासी व निडर होते हैं। ये हमेशा जीत हासिल करने के पीछे भागते हैं। माना जाता है कि ये लोग किसी से डरने व घबराने की जगह सामना करना सही समझते हैं। ऐसे में ये अपनी ताकत के बल पर जीवन में ऊंचाइयों को छूते हैं।

वृष राशि- ये लोग मस्तमौला, तेज दिमाग व आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। इन्हें मुश्किलों से डरने की जगह उसका सामना करना अच्छा लगता है। ये लोग किसी भी परिस्थिति में डरने या घबराने की जगह सोच-समझ कर फैसला लेते हैं। इसके साथ ही ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि इन्हें किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो।

सिंह राशि- सिंह राशि सूर्य देव की स्वराशि मानी जाती है। सूर्य देव सभी ग्रहों के राजा होने से सबसे शक्तिशाली होते हैं। ऐसे में इस राशि के लोगों की कुंडली में मंगल बहुत ऊंचा व मजबूत होता है। साथ ही तेज दिमाग के मालिक होने से ये लोग हर चीज का बहादुरी से सामना करते हैं। कहा जाता है कि इन लोगों को जल्दी जीत पाना हर किसी की बात नहीं है।

धनु राशि- इस राशि के लोग अपनी मर्जी से जिंदगी जीना पसंद करते हैं। इसके साथ ही ये लोग सूर्य के कुल में माने जाते हैं। ऐसे में ये बाहुबली होते हैं। इन्हें किसी भी किस्म में हार पसंद नहीं होती है। ऐसे में ये अपनी ताकत व दिमाग से जीवन में हर मुश्किल का भी आसानी से सामना कर लेते हैं। इसके अलावा ये लोग दिखने में भले ही गुस्सैल लगते हैं। मगर अंदर से नरम व खुशमिजाज होते हैं।

देश के कई राज्यों में बीयर की बिक्री में बंपर उछाल, जानिए क्या है असली वजह

नई दिल्ली। एजेंसी

बीयर इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है। बीयर की बिक्री हाल के दिनों में तेजी से बढ़ी है और यह कोविड के पहले के स्तर पर आनी शुरू हो गई है। कोविड-19 महामारी के कारण पिछले साल बीयर की बिक्री प्रभावित हुई थी। लेकिन राज्य सरकारों की एक्साइज पॉलिसीज का बीयर इंडस्ट्री पर पॉजिटिव असर दिख रहा है। रेवेन्यू के नुकसान की भरपाई के लिए राज्यों ने एक्साइज पॉलिसीज में बदलाव किया है।

इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया प्रेजिडेंट कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि पूर्वी राज्यों खासकर पश्चिम बंगाल में बीयर इंडस्ट्री 50 फीसदी की दर से बढ़ रही है। इसकी वजह यह है कि ड्यूटी स्ट्रक्चर में प्रोग्रेसिव चेंज से कीमतों में कमी आई है। उत्तरी राज्यों और दक्षिण भारत में भी कम इंफेक्शन रेट और अनुकूल टैक्स व्यवस्था के चलते कोरोना की बिक्री 2019 के स्तर पर पहुंचने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में 500 मिली की स्ट्रॉन्ग बीयर कैंस की कीमत में 70 फीसदी एक्साइज ड्यूटी है। अब इसमें करीब एक तिहाई कमी की गई है। यूपी के एक लिकर रीटेलर ने कहा कि टॉप ब्रांड का 500 मिली कैन अब 110 रुपये में मिलेगा जो पहले 130 रुपये में आता था। राज्य ने साथ ही रीटेल लाइसेंस रिन्यूवल के लिए फीस में बढ़ोतरी का प्रस्ताव नहीं किया है। होलसेल और रीटेल मार्जिन भी बढ़ा है। देश की सबसे बड़ी बीयर कंपनियों में से एक के सीनियर एग्जीक्यूटिव ने कहा कि हर तिमाही में बिक्री में सुधार आया है ओर दिसंबर तिमाही में बिक्री पिछली बार की तुलना में 15 से 20 फीसदी कम रही। जिन राज्यों ने कोरोना सेस को माफ कर दिया हैं, उनमें बिक्री बेहतर हुई है। इसी तरह देश के सबसे बड़े बीयर मार्केट्स में से एक राजस्थान में भारत में बनी विदेशी शराब पर ड्यूटी बढ़ाने की घोषणा से बीयर की बिक्री बढ़ने की संभावना है। राजस्थान ने साथ ही राज्य में बनी शराब को प्रमोट करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं।

दिल्ली में शराब खरीदने की उम्र में कमी

Grant Thornton Bharat में पार्टनर राहुल कपूर ने कहा कि दिल्ली ने शराब खरीदने और पीने के लिए उम्र सीमा कम की है। उत्तर प्रदेश में पर्सनल बार परमिट की व्यवस्था की है जिससे लोग अपने घरों में ज्यादा शराब रख सकते हैं। कई राज्यों ने एक्साइज नियमों को अपडेट किया है जिससे एल्कोहल की खपत बढ़ने की संभावना है। Simba Craft Beer के को-फाउंडर और सीईओ प्रभतेज सिंह भाटिया ने कहा, 'देश के कुछ हिस्सों में बीयर पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती से बीयर की खपत में तेजी आएगी।'

भारत से कपास और चीनी मंगाने पर मजबूर हुआ पाकिस्तान

2 साल बाद पड़ोसी को हटाना पड़ा बैन

नई दिल्ली। एजेंसी

पाकिस्तान ने दो साल बाद भारत से कपास, धागा और चीनी आयात से रोक हटा ली है। पाकिस्तान की इकॉनमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल (ECC) ने बुधवार को भारत से कपास और धागे के आयात को मंजूरी दे दी है। वहीं, प्राइवेट सेक्टर को 5 लाख टन चीनी आयात की भी छूट दी है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि घरेलू बाजार में बढ़ती कीमतों को देखते हुए पाकिस्तान को अपना फैसला बदलना पड़ा है। पाकिस्तान में लोग भारतीय कपास और चीनी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि यह उन्हें कम कीमत में मिल जाती है। दूसरे देशों से होने वाली आपूर्ति के मुकाबले भारतीय उत्पाद सस्ते हैं। भारत दुनिया में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है तो चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत को निर्यात करके जहां सरप्लस खपाने में मदद मिलेगी तो पाकिस्तान में रमजान से पहले चीनी की कीमतें कम हो जाएंगी। पाकिस्तान ने भारत से आयात को मंजूरी ऐसे समय पर दी है जब दोनों देशों के रिश्तों में पिछले कुछ समय से सुधार के संकेत मिल रहे हैं। बंटवारे के बाद से तीन युद्ध लड़ चुके दोनों देशों के बीच पिछले महीने संघर्षविराम को लागू करने पर सहमति बनी तो दोनों देशों की सेनाओं ने संयुक्त बयान जारी किया।

आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था यूआईडीएआई को मिला नया सीईओ

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

वरिष्ठ नौकरशाह सौरभ गर्ग को आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (सीईओ) नियुक्त किया गया है। केंद्र ने गुरुवार को अधिकारियों के विभागों के फेरबदल किया जिसके तहत यह नियुक्ति हुई है। गर्ग 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और फिलहाल अपने राज्य कैडर ओड़िशा में कार्यरत हैं। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने यूआईडीएआई के सीईओ के रूप में गर्ग की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। उनका रैंक और वेतनमान अतिरिक्त सचिव के स्तर का होगा। महाराष्ट्र कैडर के 1991 बैच के आईएएस अधिकारी संजीव कुमार को भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण (एएआई) का चेयरमैन नियुक्त किया गया है।

आतीश चंद्र बने एफसीआई के चेयरमैन

आदेश के अनुसार आतीश चंद्र भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक होंगे। उनका रैंक और वेतनमान अतिरिक्त सचिव के समतुल्य होगा। बिहार कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी चंद्र फिलहाल कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव हैं। विभिन्न मंत्रालयों में फेरबदल के तहत कुल 22 नौकरशाहों की नियुक्ति की गयी है।

चीन ने देश में सेमीकंडक्टर के विकास के लिये कर में कटौती की

बीजिंग। एजेंसी

चीन ने अपने सेमीकंडक्टर उद्योग को प्रोत्साहित करने एवं उसे गति देने के लिये सोमवार को कर छूट की घोषणा की। अत्याधुनिक उपकरणों तक पहुंच को लेकर अमेरिकी पाबंदियों के बीच चीन ने यह कदम उठाया है। पाबंदियों के कारण प्रौद्योगिकी कंपनी हुआवेई और कुछ अन्य कंपनियों के लिये अमेरिकी प्रोसेसर चिप तक पहुंच पर रोक लग गयी है। नेताओं ने चीन को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर शक्ति बनाने के लिये प्रयासों में तेजी लाने की घोषणा की है और यह नीति निर्माताओं के लिये शीर्ष प्राथमिकता है। अमेरिका के साथ शुल्क युद्ध के बाद स्मार्टफोन और अन्य उद्योगों के लिये अमेरिकी उपकरणों पर निर्भरता की बात सामने आयी। उसके बाद चीन अब इन उपकरणों का स्वयं विकास करने को इच्छुक है। वित्त मंत्रालय के अनुसार चिप बनाने वाली कंपनियों के लिये मशीनरी और कच्चा माल के आयात पर 2030 तक कर छूट होगी। चीन ने देश में चिप उद्योग के विकास के लिये काफी रकम खर्च की लेकिन स्मार्टफोन बनाने वाली तथा दूसरी प्रौद्योगिकी कंपनियां अभी भी अत्याधुनिक उपकरणों के लिये अमेरिका, यूरोप और ताइवान जैसे देशों पर निर्भर हैं। शुल्क युद्ध के बीच अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में हुआवेई टेक्नोलॉजीज लि. की अमेरिकी प्रोसेसर चिप और अन्य प्रौद्योगिकी तक पहुंच पर रोक लगा दी थी। प्रोसेसर चिप और अन्य सेमीकंडक्टर का चीन सबसे बड़ा आयातक है। वह सालाना इनका 300 अरब डॉलर से अधिक मूल्य का इसका निर्यात करता है।

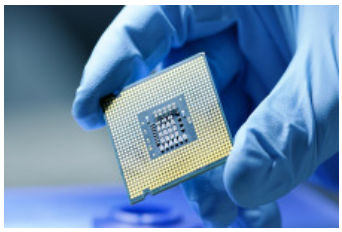

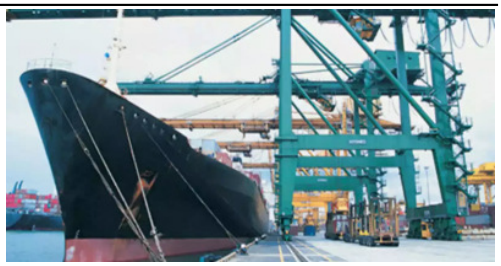

कोचीन शिपयार्ड का प. बंगाल का पोत निर्माण केंद्र जून में परिचालन में आएगा

नयी दिल्ली। एजेंसी

सार्वजनिक क्षेत्र की कोचीन शिपयार्ड को पश्चिम बंगाल में बन रहे 170 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक पोत निर्माण केंद्र के जून, 2021 तक परिचालन में आने की उम्मीद है। बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने हाल ही में भारतीय नौसेना के अगली पीढ़ी के मिसाइल पोतों के निर्माण के लिये 10,000 करोड़ रुपये के ठेके को लेकर सबसे कम की बोली लगाई है। पोत परिवहन मंत्रालय के दस्तावेज के अनुसार कोचीन शिपयार्ड लि. अपनी पूर्ण अनुषंगी हुगली कोचीन शिपयार्ड लि. (एचसीएसएल) के जरिये राज्य के नजीरगंज में आधुनिक पोत परिवहन केंद्र स्थापित कर रही है। परियोजना की अनुमानित लागत 169.76 करोड़ रुपये है। दस्तावेज में कहा गया है, "इस केंद्र के वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही तक परिचालन में आने की उम्मीद है।" एचसीएसएल का रो-रो जहाज, कार्गो जहाज, कंटेनर, यात्री जहाज आदि बनाने का लक्ष्य है। कोचीन शिपयार्ड ने विज्ञान सागर नाम से नया समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी, 2021 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया। कंपनी ने देश में वैश्विक स्तर के ड्रेजर बनाने के लिये हाल ही में ड्रेजिंग कॉरपोरेशन और आईएचसी हॉलैंड बीवी के साथ समझौता किया है। फिलहाल, भारत नदी/समुद्री से गाद निकालने के लिये विदेशी ड्रेजरों पर सालाना करीब 2,000 करोड़ रुपये खर्च करता है।

जेएनपीटी ने नया इंटर-टर्मिनल मार्ग खोला, बीएमसी को चार टर्मिनलों से जोड़ेगा

मुंबई। एजेंसी

देश के प्रमुख कंटेनर बंदरगाह जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) ने शनिवार को एक नए इंटर-टर्मिनल मार्ग को शुरू करने की घोषणा की। इसके जरिये बीएमसी टर्मिनल को बंदरगाह पर चार अन्य टर्मिनलों के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे यातायात को और बेहतर किया जा सकेगा। जेएनपीटी के चेयरमैन संजय सेठी ने इस टर्मिनल का उद्घाटन किया। इसमें मौके पर बंदरगाह के अन्य अधिकारी और सीमा शुल्क अधिकारी मौजूद थे। जेएनपीटी ने बयान में कहा कि इस टर्मिनल से बीएमसी टर्मिनल और चार अन्य टर्मिनलों के बीच कंटेनरों की आवाजाही का रास्ता पहले के पांच किलोमीटर से घटकर आधा यानी ढाई किलोमीटर रह जाएगा। जेएनपीटी पांच कंटेनर टर्मिनलों का परिचालन करता है। प्रमुख घरेलू बंदरगाहों में कुल कंटेनर कार्गो में जेएनपीटी की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से अधिक है।

कैबिनेट ने फूड प्रोसेसिंग में PLI स्कीम को दी मंजूरी

नई दिल्ली। एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में फूड प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। कैबिनेट ने फूड प्रोसेसिंग में पीएलआई स्कीम (इ्ध्ध एम्पस) को मंजूरी दी है। ये पीएलआई स्कीम सरकार अगले पांच साल तक जारी रखेगी। PLI स्कीम के तहत 10,900 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने की मंजूरी दी गई। इस स्कीम के तहत सरकार 2 से 5 फीसदी तक इंसेंटिव देगी खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए कहा, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए 10,900 करोड़ रुपए की राशि के साथ पीएलआई को मंजूरी दी गई है। यह निर्णय हमारे किसानों के लिए एक उचित समर्पण है।

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बजट में सरकार ने 12-13 क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना लाने की बात कही थी। छह क्षेत्रों के लिए पहले ही पीएलआई की घोषणा की जा चुकी है. उन्होंने कहा, आज, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए पीएलआई को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि इस घोषणा से मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, विदेशी निवेश में बढ़ोतरी होगी और किसानों को अपनी पैदावार की उचित कीमत मिलने के साथ ही बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

ढाई लाख लोगों को मिलेगा फायदा

किसानों की आमदनी बढ़ाने के तरीके ढूंढे जा रहे

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, कोविड के बावजूद देश के अन्नदाता ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में जो योगदान दिया है। उसको और बल देने के ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि के नए कानूनों में जिस तरह से हमने अपने माल बेचने के ऑप्शन दिए हैं। उसी तरह से हमने यहां भी ऑप्शन दिया है कि कैसे किसानों की आय बढ़ाई जाए। कैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ग्लोबल स्तर पर आगे बढ़े. हमारे ऑर्गेनिक फूड कैसे बाहर जाएं और किसानों को बेहतर फायदा पहुंचे।

दूसरे दौर के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए आवेदन का आज अंतिम मौका

दूसरे चरण के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च है. दूसरे दौर की पीएलआई योजना चार साल की होगी। इसके तहत प्रोत्साहन 1 अप्रैल, 2021 से दिया जाएगा। सरकार के लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिशों का सबसे ज्यादा फायदा इलेक्ट्रिक कार, बैटरियां, फूड प्रोसेसिंग और कपड़े बनाने वाली कंपनियों को होगा।

क्या है PLI स्कीम

विदेशी कंपनियों को भारत में सामान बनाने के लिए आकर्षित करने के हिसाब से सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (PLI एम्पस) शुरू की है। पीएलआई स्कीम के तहत केंद्र सरकार अगले पांच साल के दौरान भारत में सामान बनाने वाली कंपनियों को 1.46 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन देगी। इस स्कीम का लाभ सभी उभरते सेक्टर जैसे कि ऑटोमोबाइल, नेटवर्किंग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, उन्नत रसायन विज्ञान, टेलिकॉम, फार्मा और सोलर पीवी निर्माण आदि ले सकते हैं।

साइबर हमलों से निपटने के लिए भारत उठा रहा है कई कदम, विकसित कर रहा है 'देसी तकनीक'

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय रक्षा सचिव डॉ अजय कुमार ने कहा, साइबर स्पेस में होने वाले हमलों से 'आत्मनिर्भर भारत' न सिर्फ मजबूती से लड़ेगा बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बनाएगा। इसके लिए देश के तमाम प्रौद्योगिकी संस्थानों में ना सिर्फ लोगों को साइबर हमलों के बारे में जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है, बल्कि देश के तमाम स्टार्टअप्स और डीआरडीओ जैसी तमाम संस्थाओं के साथ मिलकर देसी तकनीक का विकास भी किया जा रहा है। हमारा नेटवर्क डिवाइस जितना ज्यादा सुरक्षित होगा, उतना ज्यादा साइबर हमलों को हम रोक सकेंगें।

रक्षा सचिव सोमवार को इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी एंड

इनफार्मेशन कॉन्फ्रेंस में तमाम साइबर एक्सपर्ट से रूबरू थे। अजय कुमार ने कहा कि डाटा और सूचनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इनके लीक होने से थिंकिंग पावर को मैनिपुलेट किया जा सकता है। उन्होंने माना कि साइबर सिक्योरिटी के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की आवश्यकता है, जो इस पर काम करके साइबर स्पेस को सुरक्षित रख सकें। यही वजह है सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश के अलग-अलग प्रौद्योगिकी संस्थानों में साइबर सिक्योरिटी जागरूकता और उससे संबंधित जानकारी रखने वाले कोर्सेज को पेश किया है। डॉ अजय कुमार ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से साइबरस्पेस को और ज्यादा मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनका कहना है, इसके तहत बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेज सूचना तंत्र और साइबर डाटा इनफार्मेशन लीकेज से सुरक्षित होंगी। उन्होंने बताया आईआईटी चेन्नई के साथ मिलकर इस तरीके के कई प्रयोग भी किए जा रहे हैं।

रक्षा सचिव ने कहा कि निश्चित तौर पर डाटा हमारे देश से दुनिया के अलग-अलग मुल्कों में ट्रांसफर हो रहा है। डाटा और सूचनाएं ट्रांसफर होने के बहुत से रास्ते हैं। जिसमें सोशल मीडिया से लेकर दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज से जुड़ना और उनका इस्तेमाल होना शामिल है। उन्होंने कहा कि हमें तकनीकी सौदों में इंडस्ट्री के साथ खरीददार और विक्रेता से आगे बढ़कर पार्टनरशिप के तरीके से काम करने की आवश्यकता है। जिससे हम एक ऐसे विश्वास के प्लेटफार्म पर मिलकर काम कर सके जहां पर साइबर सिक्योरिटी को तोड़ा ना जा सके।

कोरोना की रूसी वैक्सीन स्पुतनिक-V के आपातकालीन उपयोग के लिए विशेषज्ञ समिति की बैठक आज

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना वायरस की रूसी वैक्सीन स्पुतनिक-ञ के आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण आवेदन पर विचार के लिए आज विषय विशेषज्ञ समिति की बैठक आयोजित की गई है। भारत में वैक्सीन निर्माता डॉ. रेड्डी ने पहले ही तीसरे चरण के परीक्षणों की सुरक्षा और इम्युनोजेनेसिटी डेटा प्रस्तुत किया है। जी न्यूज की खबर के अनुसार फार्मा क्षेत्र की कंपनी डॉ रेड्डीज लेबोरेटरीज को उम्मीद है कि रूसी कोरोना वायरस वैक्सीन स्पूतनिक-ञ को अगले कुछ सप्ताह में भारतीय ड्रग रेगुलेटर्स से मंजूरी मिल सकती है। डॉ रेड्डीज लेबोरेटरीज के सीईओ, एपीआई और सर्विसेज दीपक सापरा ने बताया कि डॉ रेड्डीज ने स्पूतनिक-5 टीका भारत में लाने के लिए 'रशिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड' के साथ करार किया है। सापरा ने कहा, हमें अगले कुछ सप्ताह में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। यह दो खुराक का टीका होगा। आप पहली खुराक लेने के बाद दूसरी खुराक 21वें दिन लेंगे। टीका लेने के 28वें और 42वें दिन के बीच प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी. सापरा रविवार शाम को आयोजित एक वेबिनार के दौरान अपने विचार रख रहे थे जब उनसे स्पूतनिक टीके की उपलब्धता के बारे में पूछा गया तब उन्होंने यह जानकारी दी। बता दें कि इधर, भारत में कोरोना के रोजाना आने वाले मामलों में बुधवार को थोड़ी राहत मिली है। बीते 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना वायरस के 53 हजार 480 नए मामले दर्ज किए गए हैं तो वहीं इस दौरान 41 हजार 280 मरीज ठीक हो गए हैं। हालांकि, चिंता की बात यह है कि इस बीच मौत का आंकड़ा साढ़े तीन सौ पार कर गया है। वहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले एक दिन में कोरोना वायरस से 354 लोगों की जान गई है। इसी के साथ अब भारत में कोरोना वायरस के कुल 1 करोड़ 21 लाख 49 हजार 335 मामले रिपोर्ट हो चुके हैं। इनमें से 1 करोड़ 14 लाख 34 हजार 301 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं।

ICMR ने किया दावा

देश में नहीं है कोरोना वायरस का एक भी भारतीय वेरिएंट

नई दिल्ली। एजेंसी

देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में ये आग की तरह फैल रहा है। जिसके चलते हर दिन वायरस से संक्रमित लोगों के आंकड़े सामने आ रहे हैं। वहीं मरने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा देखा जा रहा है। इस स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी चिंता व्यक्त की है और लोगों से सावधान रहने की अपील की है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने घोषणा की है कि देश में अब तक कोरोना का एक भी ऐसा वेरिएंट नहीं पाया गया है जिसमें भारतीय संस्करण देखने को मिले। यानी भारत में वायरस विदेश से आया है। घ्ण्ैं के महासचिव बलराम भार्गव ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि ये कोरोना वायरस का कोई भारतीय संस्करण नहीं है और इस वजह से ही कोवाक्सिन और कोविशिल्ड वैक्सीन ने यूके और ब्राजील के वेरिएंट के खिलाफ अपना असर दिखाया है। जबकि दक्षिण अफ्रीका के वेरिएंट की वैक्सीन पर अभी भी काम चल रहा है।

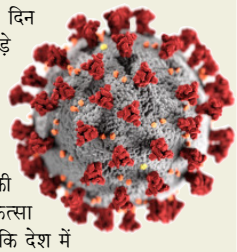

स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण का बयान

स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा जब कोई वायरस अपनी जगह से शिफ्ट होता है, तो वो महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजरता है। इसलिए परीक्षण करना जरूरी होता है जिससे ये पता चल सके कि वायरस के खिलाफ वैक्सीन कारगर है या नहीं।

कोरोना वायरस से बचाव के उपाय

कोविड 19 के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए हर व्यक्ति को पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। वायरस की दूसरी स्टेज पहली स्टेज से ज्यादा खतरनाक है और ये काफी तेजी से देश भर में फैल रहा है। इसका मुख्य केंद्र महाराष्ट्र बना हुआ है. इसलिए इस वायरस से बचने के लिए मास्क और सेनेटाइजर का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। इसके अलावा कोरोना वायरस की वैक्सीन की सारी डोज को लेना भी जरूरी है, जिससे हम स्वस्थ रहें और वायरस को दूसरों तक फैलने से रोके।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित । संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।